23 जनवरी 2018

आसियान के 50 वर्ष: कुछ विचारणीय विन्दु

*डॉ. तेमजेनमेरेन आओ तथा डॉ. धुबज्योति भट्टाचार्जी**

वर्ष 2017 आसियान की स्थापना का 50वां वर्ष था। पिछले पांच दशकों से ये संगठन अपने क्षेत्र की व्यापकता तथा क्रियाकलाप में लगातार विस्तार कर रहा है। एक बात स्पष्ट है कि आसियान की स्थापना तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हुई थी। 1967 में इस क्षेत्र में लगातार संघर्ष हो रहा था। उन परिस्थितियों में क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा समृद्धि लाने में मदद के लिए एक बहुपक्षीय संगठन के स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसके परिणामस्वरूप आसियान का गठन हुआ।

दक्षिणी-पूर्वी एशिया में पिछले पचास वर्षों में राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, साथ ही कई स्तरों में सहयोग की मांग लगातार बढ़ रही है। संगठन के उद्भव में विस्तार एक व्यापक परिणाम के रूप में सामने आया है। इस प्रक्रिया में आसियान एक सुनिश्चित भौतिक स्थान तथा क्षेत्रीयतावाद की भावना उत्पन्न करने में सक्षम हुआ है, जो उसके आसपास के पड़ोसियों से भिन्न है। वैश्वीकरण विरोधी तथा संरक्षणवाद में विस्तार को देखते हुए विभिन्न देशों के समुदाय का निर्माण करने तथा उसे मजबूत बनाने की विशेष आवश्यकता है। वैश्विक एकत्रीकरण का विकास आसियान के लिए बहुपक्षवाद के आदर्शों तथा बहुपक्षवाद प्रणाली के संरक्षण में सहायक साबित हो रहा है, जो अब तक इस क्षेत्रीय समूह को लाभान्वित करता रहा है। इस प्रकार, ये संगठन में अंदरूनी तथा बाह्य आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग का स्वरूप है, जिसे मजबूत करने के साथ नई वास्तविकताओं तथा चुनौतियों के साथ अनुकूलन भी करना होगा।

इस संदर्भ में यह आलेख आसियान के उन दोहरे उद्देश्यों की समीक्षा करेगा, जिसके लिए 1967 में इसका गठन हुआ था, यानी आर्थिक सम्पन्नता तथा शांति में वृद्धि। सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था आसियान के मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं, तथा इस संदर्भ में ये आलेख 2017 में आसियान की विभिन्न मंत्री स्तरीय बैठकों के

परिणामों को शामिल करेगा, ताकि वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इस संगठन का उद्भव समझा जा सके।

आर्थिक आयाम

एशिया प्रशांत क्षेत्र में बदलते आर्थिक तथा रणनीतिक आयामों के साथ आसियान को अपने गठन के मूल कारणों के साथ अपनी गतिविधियों तथा सहयोग में विस्तार की सख्त आवश्यकता महसूस हुई। 1972 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम ने सिफारिश की, कि आसियान के सदस्य देशों को क्षेत्रीय स्तर पर निकटवर्ती क्षेत्रीय आर्थिक समन्वय द्वारा औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इन उपायों में तरजीही कर व्यवस्था के आदान-प्रदान द्वारा व्यापारिक उदारीकरण, पूरक समझौते तथा परियोजनाओं में क्षेत्रीय निवेश सम्मिलित थे। 1976 में बाली शिखर सम्मेलन में आसियान नेताओं ने दो ऐतिहासिक संधियां कीं, जो आपसी आर्थिक सहयोग में तेजी लाने में मददगार रहीं। ये थीं दक्षिणी-पूर्वी एशिया में भाईचारा तथा सहयोग की संधि (ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोओपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया - टीएसी), तथा आसियान समझौते की घोषणा। दोनों संधियों में आर्थिक क्षेत्र में अनिवार्य रूप से सक्रिय प्रोत्साहन तथा सहयोग की बात कही गई, जिनमें आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग भी शामिल थे। आसियान में निकटवर्ती आर्थिक समन्वय इस तर्क पर आधारित था, कि आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में एक विशाल सम्मिलित आसियान बाजार, औद्योगिक विकास तथा अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार इसका दीर्घकालीन लक्ष्य यूरोपीय संघ की तर्ज पर दक्षिणी-पूर्वी एशिया में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा सामूहिक व्यापार स्थापित करना था।

वैश्वीकरण आरम्भ होने के साथ आसियान ने 1990 के प्रारम्भिक वर्षों में बाजार-चालित तथा निर्यातोन्मुख विकास कार्यक्रमों के अनुरूप विस्तृत आर्थिक समन्वय की आवश्यकता महसूस की। आर्थिक सहयोग ने आसियान कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी तथा इसने 1992 में आसियान में मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि (आसियान फ्री ट्रेड एग्रिमेंट - एएफटीए) स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका उद्देश्य अंतर-क्षेत्रीय व्यापार में कर से जुड़ी सभी बाधाएं दूर करना था। 20 नवम्बर 2007 को सिंगापुर में 7वें शिखर सम्मेलन के दौरान जारी आसियान घोषणापत्र मील का पत्थर बना, क्योंकि इसने न सिर्फ आसियान विनियमन, नियमों तथा मूल्यों को आकार देने में मदद की, बल्कि आसियान समुदाय निर्माण में सहयोग के लिए एक सुनिश्चित संस्थागत ढांचा तैयार किया। एएफटीए तथा उसके पश्चात आसियान आर्थिक परियोजनाएं 2015 में आसियान आर्थिक समुदाय (आसियान इकोनॉमिक कम्यूनिटी - एईसी) स्थापित करने में काफी मददगार साबित हुईं। आर्थिक विकास प्राप्त करने की दिशा में इस बहुपक्षीय दृष्टिकोण ने सकारात्मक योगदान दिया है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में आसियान की अर्थव्यवस्थाओं ने भारी वृद्धि दर्ज की, जिसकी 2016 में वैश्विक घरेलू सकल उत्पाद में हिस्सेदारी 3.3 प्रतिशत थी। शांतिपूर्ण सहयोग की भावना को 'आसियान मार्ग' करार दिया गया है तथा पिछले पचास वर्षों में इसने महत्वपूर्ण विकास किया है। आज की तारीख में आसियान दुनिया में तीसरी सर्वाधिक श्रम शक्ति के साथ सातवें सबसे बड़े बाजार का प्रतिनिधित्व करता है तथा 2030 तक इसके दुनिया के चौथे सबसे बड़े आर्थिक गुट बनने की आशा है।

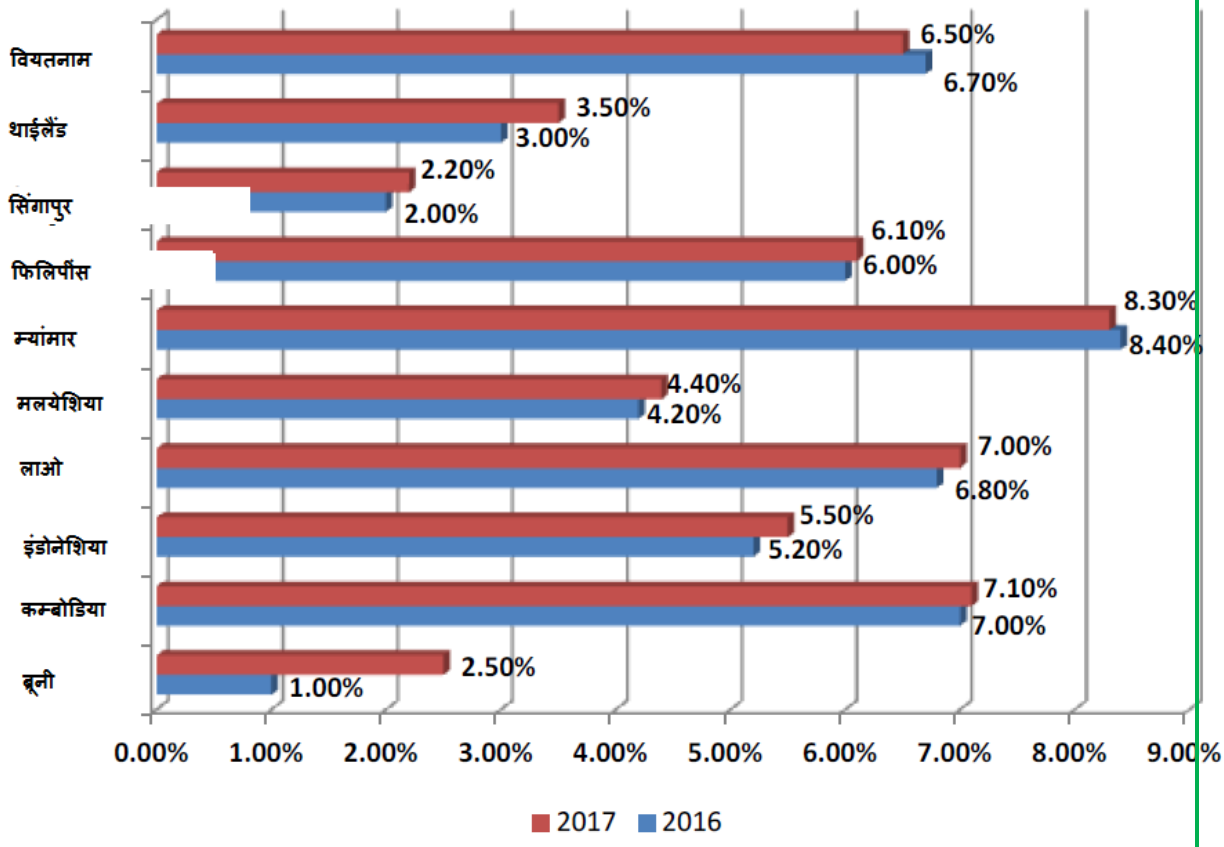

आकृति1 : आसियान देशों के घरेलू सकल उत्पाद में वृद्धि 2016-17

आसियान देशों के निजी सकल घरेलू उत्पाद के साथ तुलना की जाए तो जैसा आकृति में दिखाया गया है, ये वृद्धि तुलनात्मक दृष्टि से तेज है। एशियाई विकास बैंक के आंकड़ों के अनुसार बार आरेख में देखा जा सकता है कि 2016 तथा 2017 के बीच सभी आसियान देशों के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती रही। इनमें म्यांमार तथा वियतनाम शामिल नहीं हैं, जहां पहले से ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर अधिक है। आसियान देशों की महत्वपूर्ण सकारात्मक आर्थिक उपलब्धियों में, किसी क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता में वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो सकता है। 13 नवंबर 2017 को मनीला में आयोजित 31 वें आसियान शिखर सम्मेलन में, सदस्यों ने आसियान की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि के दृष्टिकोण का स्वागत किया, जिसकी 2017 में अनुमानित दर पांच प्रतिशत थी। 2016 के अंत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 98 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 25.2 प्रतिशत अंतर-आसियान निवेश था। 2017 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि इस क्षेत्र में निवेशकों के बढ़ते आत्मविश्वास तथा वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आशाओं के अनुरूप लाभ वसूली की उम्मीद के कारण है।

इसके अलावा 2016 में आसियान देशों का वाणिज्यिक व्यापार 2.2 खरब डॉलर रहा, जिसमें 23.1 प्रतिशत अंतर-आसियान देशों के बीच व्यापार था। इसकी तुलना यूरोपीय संघ के साथ की जाए तो 2015 में अंतर-यूरोपीय संघ का व्यापार 63 प्रतिशत था, क्योंकि पारम्परिक रूप से यूरोपीय संघ के सदस्य देश संघ से बाहर व्यापार करने के बजाय आपस में ही व्यापार को प्रमुखता देते हैं।

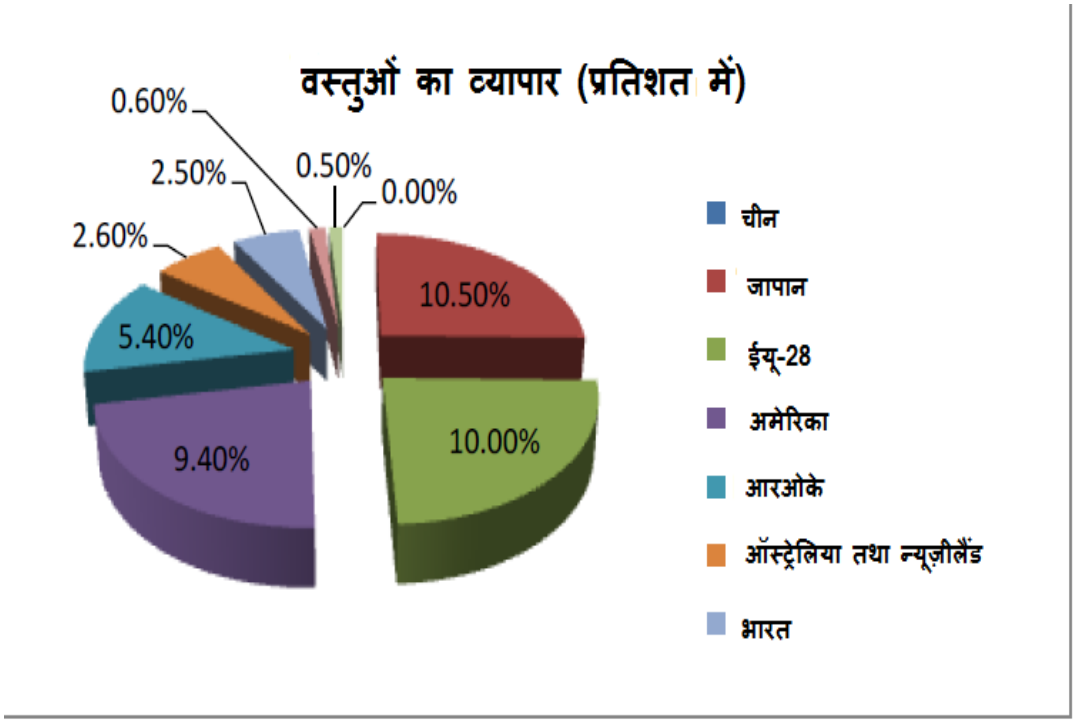

आकृति2 : वार्ता सहयोगियों के साथ वस्तुओं में आसियान का व्यापार

आकृति 2 में पाई चार्ट आसियान का अपने अपने संवाद भागीदारों के साथ प्रतिशत में व्यापार इंगित करता है। चीन आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका कुल व्यापार 345,416 मिलियन अमेरिकी डॉलर है तथा जो व्यापार का 15% हिस्सेदार है। इसके बाद जापान, ईयू-28, अमेरिका, कोरियाई रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड और भारत की बारी आती है, जिनका कुल व्यापार 58.584 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और जिनकी हिस्सेदारी 2.5% है। जहां तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रश्न है तो 2015 के अंत तक आसियान में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से कुल आमदनी 18.4% थी। इसमें 16.7% के साथ यूरोपीय संघ की भागीदारी सर्वाधिक थी, जिसके बाद जापान (14.5%), अमेरिका (11.3%) तथा चीन (6.8%) की बारी आती है। आसियान के पूर्व महासचिव ले लियोंग मिन्ह के अनुसार आसियान के आर्थिक समन्वय की सफलता सिर्फ उसकी आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर नहीं आंकी जानी चाहिए, बल्कि इसके सदस्य देशों के पारस्परिक लाभ को देखते हुए भी तय किया जाना चाहिए। श्री मिन्ह का कहना है कि क्षेत्र की आर्थिक गतिशीलता बनाए रखने के लिए आसियान का प्रयास हमेशा समानता के विचार, क्षमता निर्माण पर बल देना तथा तकनीकी मदद देने की रही है। इसके अतिरिक्त आसियान के बाह्य आर्थिक सम्बंध तय करने के लिए सुसंगत तथा विस्तृत दृष्टिकोण का आधार वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण के साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण का मेल करना है।

आसियान तथा उसके छह एफटीए सहयोगियों के साथ समयबद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए वर्तमान मुक्त व्यापार संधियों के कार्यक्षेत्र के विस्तार में आसियान क्षेत्रीय एकीकृत आर्थिक सहयोग (आरसीईपी) बढ़ाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। यदि आसियान यूरोपीय संघ की तर्ज पर एक बाजार स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है तो ये कदम आवश्यक हैं। यूरोपीय संघ का एकल बाजार या अंदरूनी बाजार में वस्तु, सेवाएं, पूंजी तथा लोगों का स्वतंत्र आवागमन होता है। वस्तुओं के मुक्त परिवहन के सिद्धांत के अनुसार यूरोपीय संघ के भीतर वस्तुओं के आवागमन के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का बंधन नहीं होता। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के एकल बाजार होने तथा एकमात्र बाह्य सीमा होने के कारण उनकी व्यापार

नीति भी एक ही है। इस प्रकार वो विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ सामूहिक रूप से व्यापारिक समझौते करते हैं।

आर्थिक एकीकरण के लिए नीति निर्धारण

- आसियान शिखर सम्मेलन में नेताओं ने आसियान के नेतृत्ववाले विस्तृत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए आरसीईपी की भारी संभावनाओं के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। उन्होंने आरसीईपी की वार्ताओं में आसियान की केन्द्रीय भूमिका को दोहराया तथा आरसीईपी में भागीदार देशों को 2018 की आरसीईपी वार्ता को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयास तेज करने की अपील की।

- 14 नवम्बर 2017 को सम्पन्न आरसीईपी शिखर सम्मेलन में ये उल्लेख किया गया था कि हाल में वैश्विक मंदी, बढ़ते सुरक्षावाद तथा वैश्वीकरण विरोधी भावनाओं के बावजूद आसियान देशों तथा आसियान मुक्त व्यापार समझौते के सहयोगी देशों - ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, कोरिया तथा न्यूज़ीलैंड की अर्थव्यवस्थाओं में शेष दुनिया की तुलना में तेज विकास जारी रहा। इस प्रकार नेताओं ने आरसीईपी की भारी संभावनाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई, जिसके 16 भागीदार देशों में दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या बसती है, 31.6% वैश्विक उत्पादन, 28.5% वैश्विक व्यापार होता है तथा जहां 2016 में पूरी दुनिया की तुलना में पांचवां हिस्सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। उन्होंने अर्थव्यवस्था में समान विकास के लिए आरसीईपी की संभावनाओं पर अपना विश्वास दोहराया, जो भविष्य में उनके तीन महत्त्वपूर्ण स्तम्भों की मदद से अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत कर समयबद्ध परिणाम देगा। वो तीन स्तम्भ हैं - बाजार तक पहुंच, नियम तथा सहयोग। 5 अगस्त 2017 को मनीला में आयोजित 50वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में सभी क्षेत्रों में मजबूती लाने के तौर-तरीकों की सराहना की गई, जिनमें परिवहन लिंक, खनिज ट्रस्ट फंड का निर्माण, ऊर्जा संयोजकता में वृद्धि, अधिक क्रियाशीलता, रचनात्मक तथा नूतन आईसीटी, नवीन, प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवसायिक, दीर्घकालीन तथा आर्थिक रूप से एकीकृत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रणालियों को अपनाना, साथ ही एक-दूसरे के पर्यटन उद्योग का विकास करना तथा सहारा देना, एवं पूरे क्षेत्र में वित्तीय नेटवर्क तथा सेवाओं का निर्माण (आसियान बैंकिंग एकीकरण ढांचा) करना शामिल हैं। आसियान में खाद्य, कृषि तथा एमएसएमई के विकास में सहयोग करने तथा मजबूती लाने पर भी बल दिया गया।

- 12वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन (ईएएस) में जारी बयान में भी इस क्षेत्र में संयोजन की विभिन्न रणनीतियों के बीच सहभागिता अधिक बढ़ाने को महत्त्व दिया गया। 12वें ईएएस ने पूर्वी एशिया में व्यापार, निवेश तथा सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत ढांचागत विकास पर बल दिया तथा ये स्वीकार किया कि मूलभूत ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए साधनों की अत्यंत आवश्यकता है।

- 2015 में आरम्भ किया गया आसियान आर्थिक समुदाय भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसने क्षेत्र के विकास पर बल दिया है तथा भविष्य में इसे अधिक मजबूत बनाकर, एकीकृत कर तथा संगठित कर आसियान को एक वैश्विक ताकत बनाने के लिए रोड मैप को गति प्रदान की है। 31वें आसियान शिखर सम्मेलन में ये स्पष्ट किया गया कि 23 एईसी 2025 कार्य योजनाएं सुचारु रूप से चल रही हैं, जो पहले से जारी एईसी ब्लूप्रिंट 2025 को लागू करने का प्रयास हैं। इनमें कुछ कार्य योजनाओं में आसियान कराधान सहयोग के लिए रणनीतिक कार्य योजना 2016-25 की एईसी परिषद, आसियान 2025 व्यापार सुविधा रणनीतिक कार्य योजना तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य 2017-25 के लिए आसियान कार्यक्रम शामिल हैं। एईसी 2025 निगरानी तथा निरूपण (एम एंड ई) ढांचे के आधार पर 2017 की प्राथमिकताओं समेत इन सभी क्षेत्रों में कार्यों का कार्यान्वयन किया गया है।

आर्थिक एकता के समक्ष चुनौतियां

आसियान देशों में विकास को रफ्तार देने के लिए क्षमता विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उदाहरण के लिए पिछले कुछ दशकों में आसियान में निर्माण गतिविधियों ने क्षेत्र के आर्थिक विकास को हवा दी है। हालांकि विकास के इस नमूने को आधुनिक तकनीकी द्वारा उत्पादन में होनेवाले विकास से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नई खोज, जैसे रोबोटिक स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट जैसे नवाचारों को न सिर्फ भौतिक रूप में, बल्कि क्षमता तथा क्षमता निर्माण के संदर्भ में भी आवश्यक ढांचे की आवश्यकता होती है। चुनौतियां दूर करने तथा आसियान के प्रत्येक देश अपने व्यापार तथा आर्थिक विकास तेज करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां अपनाकर उनके अनुरूप तैयार करने के लिए विस्तृत आपसी सहयोग की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ की तर्ज पर एक आम मुद्रा या एक आम बैंकिंग की प्रणाली लागू नहीं है, तथा आसियान की अर्थव्यवस्था सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है।

इनके अलावा पश्चिम में संरक्षणवाद तथा वैश्वीकरण-विरोधी वातावरण आर्थिक विकास तथा एकीकरण के रास्ते में बड़ी चुनौती है। 7 अगस्त 2017 को 18वें आसियान प्लस थ्री (एटीपी) के विदेश मंत्रियों की बैठक में जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो ने "वित्तीय तथा आर्थिक मोर्चे" पर एटीपी की संधियों का स्वागत किया ताकि इन देशों को आसियान के साथ मुक्त व्यापार संधि में सहयोग के लिए उत्प्रेरित किया जा सके। टोक्यो भविष्य में क्षेत्रीय अथवा वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका से आसियान देशों, चीन तथा दक्षिण कोरिया के साथ घनिष्टतापूर्वक सहयोग के लिए राजी हो गया है। जापान ने ये भी कहा कि वो व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जानेवाले कदमों का खुलकर विरोध करता है तथा "बढ़ते संरक्षणवाद" का पूरी तरह विरोध करेगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि "वैश्वीकरण विरोध तथा उभरते हुए संरक्षणवाद के परिप्रेक्ष्य में, दस तथा तीन देशों के लिए ये आवश्यक है कि वो पूर्वी एशियाई समुदाय को प्रायोगिक सहयोग देने तथा प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदारी उठाएं"। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विदेश मंत्री कांग क्युंग-व्हा ने कहा कि आज आसियान दिन समस्याओं का सामना कर रहा है वो "पहले की तुलना में अधिक पेचीदे तथा आपस में जुड़े हुए हैं"। उन्होंने आतंकवाद, वैश्वीकरण विरोधी भावनाओं तथा बढ़ते संरक्षणवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि ये "वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता तथा राजनीतिक अस्थायित्व का कारण हैं"।

सुरक्षा आयाम

सुरक्षा तथा स्थायित्व बनाए रखने के संघ की दो मुख्य उद्देश्यों को पारम्परिक तथा अपारम्परिक माध्यमों से चुनौतियां मिलनी जारी हैं। आसियान देशों के बीच लगातार जारी समुद्री सीमाओं तथा भूमि सीमाओं के विवाद के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा पर दबाव बना हुआ है। क्षेत्र में विभिन्न उग्रपंथी समूहों की भूमि पर तथा समुद्र में बढ़ती गतिविधियां भी चिन्ता का कारण हैं। इस प्रकार, सुरक्षा चुनौतियों ने एक प्रकार से आसियान देशों को अपने सुरक्षा मदों में अधिक व्यय करने पर मजबूर कर दिया है। सिपरी के आकलन के अनुसार, एशिया तथा समुद्रतटीय क्षेत्रों में 2016 में सैन्य मदों में व्यय 450 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 41.9 अरब डॉलर दक्षिणी-पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में व्यय किया गया था। सिपरी के आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि 2015-16 के बीच दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों में सैनिक मदों में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2007-16 के बीच विश्लेषण किया जाए तो इस क्षेत्र में सैन्य मदों में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आकृति 3 से स्पष्ट है कि पारम्परिक रूप से सैनिक मदों में अधिक व्यय करनेवाले आसियान के सदस्य देशों - इंडोनेशिया, मलयेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड ने 1992-2016 के बीच सैन्य मदों में खर्च किस तरह बढ़ाया है।

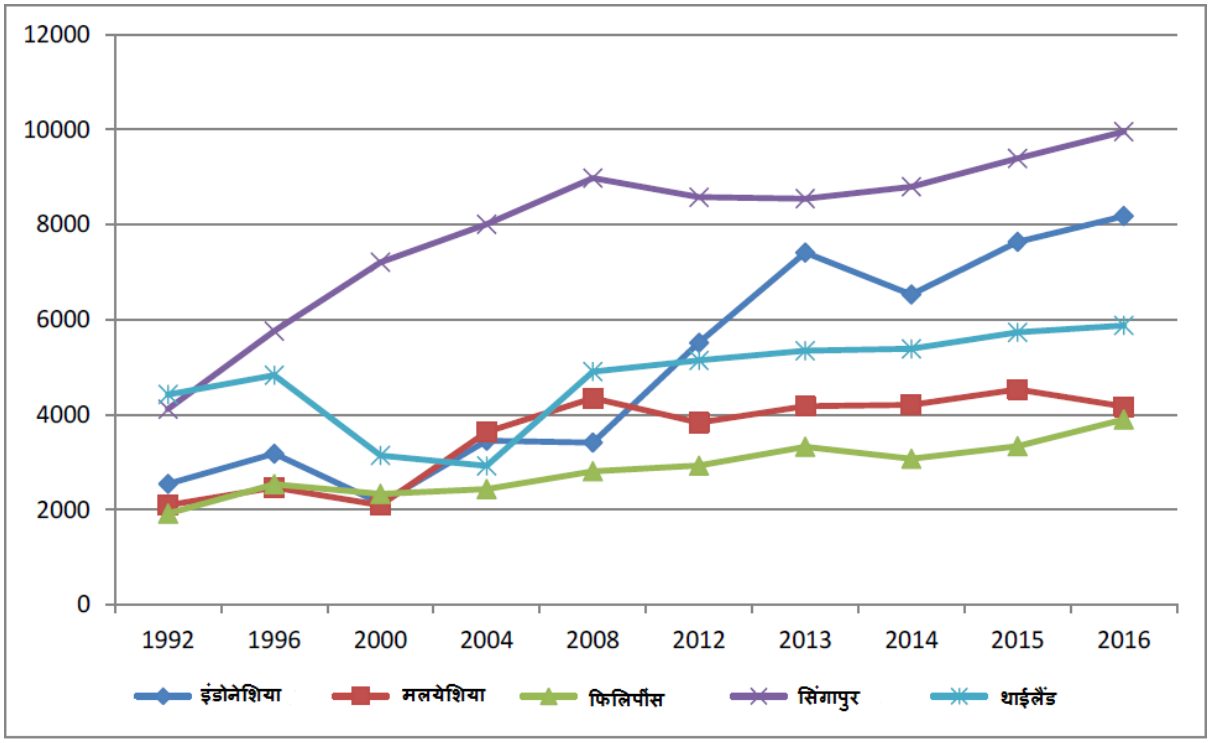

आकृति3 : देशों द्वारा सैन्य मदों में खर्च, 1992-2016 (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

आसियान के पांच सदस्य देशों में सैन्य खर्च बढ़ती गया है। थाईलैंड 1980 के दशक में तथा 1990 के आरम्भिक वर्षों में सैन्य मद में सर्वाधिक खर्च करनेवाला देश था। हालांकि 1995 के बाद पहले सिंगापुर तथा उसके बाद इंडोनेशिया ने थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया। एशियाई वित्तीय मंदी जैसे कारकों के कारण सैन्य मदों में कटौती अवश्य हुई, परन्तु बाह्य तथा अंदरूनी सुरक्षा चुनौतियों के कारण आसियान के पांच देशों में सैन्य बजट लगातार बढ़ता रहा।

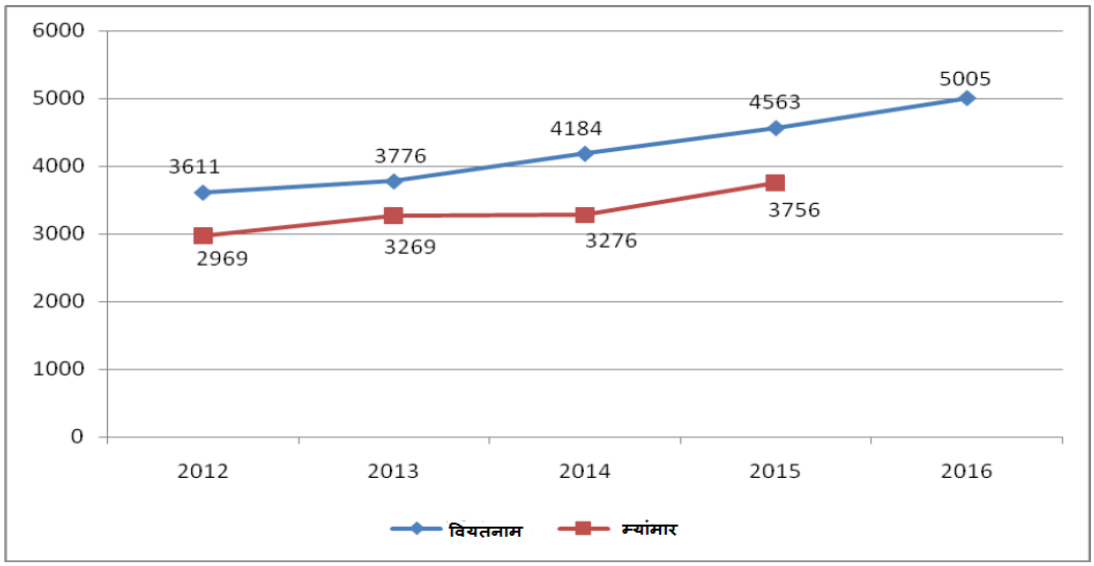

आकृति4 : वियतनाम तथा म्यांमार के सैनिक खर्च, 2012-16 (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

जैसा आकृति 4 से स्पष्ट है आसियान देशों में सैन्य मदों में खर्च बढ़ानेवाले अन्य देश हैं वियतनाम तथा म्यांमार। म्यांमार को थाईलैंड के साथ सीमा विवाद के अलावा अंदरूनी सुरक्षा चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। उधर वियतनाम का दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ समुद्री सीमा विवाद बढ़ रहा है, तथा वो विवादास्पद समुद्री क्षेत्रों में सैन्यीकरण के विरुद्ध आवाज उठानेवाले आसियान देशों में से एक है। इस क्षेत्र में आज की तारीख में कुछ प्रमुख सुरक्षा सरोकार, जिनके कारण रक्षा मदों में व्यय बढ़ा है तथा इन चुनौतियों से निपटने के लिए नई नीतियां बनानी पड़ी हैं, निम्नलिखित हैं:

अनसुलझा दक्षिणी चीन सागर विवाद

सिपरी के अनुसार दक्षिणी चीन सागर में चीन तथा कई दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों के साथ विवाद के कारण विभिन्न देशों की सरकारें अपनी सैन्य क्षमता तथा रक्षा मद के खर्च में वृद्धि को न्यायोचित ठहरा रही हैं। दक्षिणी-पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास दर में तेजी के कारण भी आसियान के सदस्य देशों में सैन्य मद में अधिक व्यय करना संभव हुआ है। 6 अगस्त 2017 को मनीला में आसियान विदेश मंत्रियों के 50वें सम्मेलन में दक्षिणी चीन सागर के लिए आचरण संहिता के ढांचे पर सहमति बनी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने स्पष्ट किया कि ये ढांचा क्षेत्रीय विवाद हल करने का साधन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आपसी विश्वास, सहयोग तथा आत्मविश्वास, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने तथा विवादों के शांतिपूर्ण हल का उचित वातावरण तैयार करने के लिए प्रबंधन करना है।

सीओसी कानूनी रूप से बाध्य नहीं है तथा क्षेत्रीय विवाद अथवा समुद्री क्षेत्र से जुड़े विवाद के मुद्दों को हल करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये नियमों पर आधारित दस्तावेज है, जिसमें विवादास्पद जल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सम्बंधित गुटों के लिए निर्देश तथा मानदंड सन्निहित हैं। इस प्रकार, ये दस्तावेज एक घोषणा मात्र है, जो दावेदारों को संयम बरतने तथा दक्षिणी चीन सागर में नए अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने पर बल देता है।

अप्रैल 2017 में आसियान के तीसवें शिखर सम्मेलन में फिलिपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर ने क्षेत्र में उभरते विवादों का उल्लेख करने से परहेज किया तथा इसके बदले आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय (एपीएससी) में मजबूती लाने तथा आसिया सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय पर ब्लूप्रिंट लाने की बात की। अध्यक्ष के बयान में सैनिकीकरण तथा कृत्रिम द्वीप के निर्माण के विषय नहीं थे। सदस्य देशों ने अपने सम्बंधित नागरिक समाजों के प्रति अधिक जवाबदेही तथा पारदर्शिता और क्षमता निर्माण पर बल दिया। ये कहा गया कि कुछेक आसियान नेतृत्व में एक आम भावना थी कि जिन विवादों पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। हालांकि अगस्त 2017 में पचासवीं वर्षगांठ के उत्सव के दौरान आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में जारी वक्तव्य तथा 13 नवम्बर 2017 को 31वें आसियान शिखर सम्मेलन में अध्यक्ष के वक्तव्य में जानबूझकर विवादास्पद संदर्भों से बचा गया। सैन्यीकरण तथा कृत्रिम द्वीप निर्माण के मुद्दों (बिना किसी देश का नाम लिये) की आलोचना की गई तथा हाल में क्षेत्रीय विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए तैयार आचार संहिता के ढांचे का समर्थन किया गया, हालांकि जो कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा या दस्तावेज नहीं है।

7 अगस्त 2017 को मनीला में आयोजित 24वें आसियान क्षेत्रीय फोरम (एआरएफ) में मंत्रियों ने आसियान तथा उसके सहयोगियों के बीच बेहतर समुद्री सहयोग का स्वागत किया। उन्होंने आसियान तथा चीन के बीच

बेहतर होते सहयोग का भी स्वागत किया तथा दक्षिणी चीन सागर पर आचार संहिता (सीओसी) के ढांचे के अन्तर्गत समझौते करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्रियों ने दक्षिणी चीन सागर में शांति, स्थायित्व तथा दीर्घकालीन विकास स्थापित करने के लाभ महसूस किये।

क्षेत्रीय सुरक्षा का उदाहरण स्थापित करने तथा दक्षिणी चीन सागर को लेकर क्षेत्र में अविश्वास तथा कड़वाहट दूर करने के मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में संयम बरतने तथा अंतरराष्ट्रीय नियमों (यूएनसीएरओएस) के अनुरूप विवाद का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने पर बल दिया गया। वक्तव्य में शांति स्थापना तथा प्रोत्साहन, सुरक्षा, स्थायित्व तथा नौका-परिवहन की संरक्षा एवं स्वतंत्रता के अलावा दक्षिणी चीन सागर पर उड़ान भरने पर भी बल दिया गया। पारस्परिक रूप से सहमत समयसीमा में एक प्रभावशाली सीओसी की स्थापना के लिए आसियान देशों तथा चीन के बीच असैन्यीकरण तथा आचार संहिता पर समझौते की आवश्यकता है। वक्तव्य में संयुक्त बयान लागू करने तथा दक्षिणी चीन सागर में अनियोजित मुठभेड़ (कोड फॉर अनप्लैन्ड एनकाउंटर एट सी - सीयूईसी) के लिए आचार संहिता का पालन करने के लिए तत्परता दिखाई गई।

24 अक्टूबर 2017 को आयोजित एडीएमएम प्लस की बैठक में समुद्री सुरक्षा पर प्रायोगिक सहयोग तथा समझौते के लिए संयुक्त प्रयास की बात की गई। बैठक में दक्षिणी चीन सागर में आचार संहिता के घोषणापत्र (डिक्लेयरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज़ इन द साउथ चाइना सी - डीओसी) को प्रभावशाली तरह से लागू करने तथा दक्षिणी चीन सागर में आचार संहिता को जल्द परिणाम तक पहुंचाने की बात की गई, ताकि क्षेत्र में आपसी विश्वास, सहयोग, शांति स्थापना, सुरक्षा तथा स्थायित्व कायम हो। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, असैन्यीकरण तथा आत्म-संयम के साथ-साथ 1982 के यूएनसीएलओएस समेत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आदर्शों के अनुरूप कानूनी तथा कूटनीतिक प्रक्रियाओं का पूर्ण सम्मान किया जाए।

आतंकवाद की चुनौतियों का सामना

आतंकवादी हमलों की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों ने भी आसियान देशों को अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण तथा उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी समझौते तथा सहयोग के रूप में आसियान के उत्तरदायित्व में विस्तार के लिए विवश किया है। हाल में दक्षिण फिलिपींस के प्रांत मारवी की तीन महीने की घेराबंदी ने आसियान देशों को आपसी सहयोग के प्रयास स्वरूप चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता महसूस करने को विवश किया। कट्टरपंथ तथा आतंकवाद के हिंसक स्वरूप तथा विदेशी आतंकवादी लड़ाकों (फॉरेन टेरोरिस्ट फाइटर्स - एफटीएफएस), एवं क्षेत्र में सीमा-पार आतंकवाद जैसी अन्य सुरक्षा चुनौतियों के खतरों पर चर्चा करते हुए आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की नवीनतम बैठक में वक्तव्य जारी किया गया कि आगामी मंत्री स्तरीय बैठक में आसियान की संशोधित आतंकवाद-रोधी समेकित कार्य योजना (आसियान कॉम्प्रिहेंसिव प्लैन ऑफ एक्शन ऑन काउंटर-टेरोरिज्म - एसीपीओए ऑन सीटी) तैयार की जाएगी। 23 अक्टूबर 2017 को मनीला के उत्तर में स्थित क्लार्क फ्रीपोर्ट में सम्पन्न आसियान रक्षा मंत्रियों की 11वीं बैठक (एडीएमएम) में *सिंगापुर ने एडीएमएम की अध्यक्षता ग्रहण की। वहां के रक्षा मंत्री नेग इंग हेन ने कहा कि वो तीन 'मुख्य विन्दुओं' पर ध्यान केन्द्रित करेंगे: क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी सहयोग को प्रोत्साहन, सामूहिक रूप से रासायनिक, जैविक तथा रेडियोधर्मी खतरों से निपटने की क्षमता का विकास तथा हवाई और समुद्री क्षेत्रों में प्रायोगिक विश्वास-निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।*

सिंगापुर ने कहा कि वो एडीएमएम की अध्यक्षता के दौरान विशेषकर आसियान के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग स्थापित करेगा। *धार्मिक कट्टरवाद तथा क्षेत्र में आतंकवाद के उद्भव को आसियान की सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है।* इसी प्रकार, एडीएमएम में इंडोनेशिया ने एक "मिनी-इंटरपोल" के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसमें क्षेत्र के छह देश "आवर आई" के द्वारा खुफिया सूचनाएं साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रत्येक देश आपस में सूचनाएं साझा करने के लिए नई ईकाई का गठन करेगा, जबकि प्रत्येक देश से इस कार्य के लिए निर्धारित व्यक्ति हर रोज सामूहिक सूचनाएं साझा करेगा। 7 अगस्त 2017 को सम्पन्न एआरएफ की बैठक में अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में आतंकवाद रोधी तथा बहुदेशीय अपराधों से निपटने की कार्य योजना के विषय में बताया।

एआरएफ की बैठक में उपस्थित सभी गुटों ने आतंकवाद रोधी आसियान सम्मेलन (आसियान कन्वेशन ऑन काउंटर टेरोरिज़्म - एसीसीटी) के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रियों ने आपसी सहयोग बढ़ाने तथा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति (जीसीटीएस) के आधार पर आतंकवाद रोकने तथा दबाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने पर पूरी प्रतिबद्धता जताई।

कोरियाई प्रायद्वीप

24वें एआरएफ में कोरियाई प्रायद्वीप की गतिविधियां विषय वस्तु के केन्द्र में रहीं, जिसमें सदस्यों ने एक स्वर में कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह, संतोषजनक निरीक्षण योग्य तथा अपरिवर्तनीय परमाणु अप्रसार करने पर बल दिया। साथ ही आत्मसंयम बरतने तथा तनाव कम करने के लिए वार्ता का वातावरण तैयार करने का भी आह्वान किया। एआरएफ ने उत्तरी कोरिया को आसियान क्षेत्रीय फोरम में भागीदारी के लिए भी आमंत्रित किया, ताकि दीर्घकालीन शांति, स्थायित्व, मित्रता तथा क्षेत्र की सम्पन्नता की दिशा में सकारात्मक योगदान दिया जा सके।

मंत्रियों ने सकारात्मक वार्ता तथा आपसी हितों के राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर सहयोग तथा एशिया-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के मुद्दों पर विचार के लिए एआरएफ के महत्त्व पर बल दिया। मंत्रियों ने एआरएफ विजन वक्तव्य के साथ-साथ एआरएफ कार्य योजनाओं के अन्तर्गत सम्बंधित प्राथमिकताओं को एआरएफ की प्रक्रियाओं के भीतर हनोई योजना के व्यापक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए तथा रासायनिक हथियारों का जमावड़ा समाप्त करने और उन्हें समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। 13 नवम्बर 2017 को सम्पन्न आसियान शिखर सम्मेलन में दक्षिणी-पूर्वी एशिया में अखंडता तथा सहयोग की संधि (ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोओपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया - टीएसी) को क्षेत्र के आंतरिक सम्बंधों के प्रशासन की मुख्य संहिता बनाने तथा क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के आधार बनाने की बात कही गई। वक्तव्य में आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय (एपीएससी) ब्लूप्रिंट 2025 को 75% लागू करने की सराहना की गई। साथ ही दक्षिणी-पूर्वी एशिया को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने की संधि (ट्रीटी ऑन द साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर-वीपन फ्री ज़ोन - एसईएएलडब्ल्यूएफज़ेड) लागू करने की समयसीमा बनाने पर सहमति बनी।

समुद्री सुरक्षा की चुनौती

पेचीदे खतरों तथा किसी एक देश की तुलना में समुद्र के काफी विशाल होने के कारण समुद्री सुरक्षा एक प्रमुख आवश्यकता बन गई है। समुद्री डाका, नशीली दवाओं तथा हथियारों की तस्करी, मछली समेत अन्य संसाधनों का अवैध कारोबार, तथा मनमाने तरीके से संसाधनों की खोज एवं निष्कर्षण पर रोकथाम की चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्टूबर 2017 में हुई एडीएमएम प्लस की 4थी बैठक में एचएडीआर समेत

समुद्री सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही समुद्री तथा साइबर क्षेत्र में नई चुनौतियों का उल्लेख किया गया। समुद्री सुरक्षा और सहयोग के विषय पर आसियान के सभी देशों ने 'सामूहिक हितों तथा सरोकारों, समुद्री वैज्ञानिक शोध, समुद्री डोमेन जागरुकता एवं समुद्री पर्यावरण के संरक्षण पर लगातार सकारात्मक वार्ता' की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने इंडोनेशिया, मलयेशिया तथा फिलिपींस द्वारा त्रिपक्षीय सहयोग व्यवस्था (ट्राइलैटरल कोओपरेटिव अरेंजमेंट - टीसीए) के अन्तर्गत की तर्ज पर संयुक्त समुद्री गश्त का स्वागत किया। वक्तव्य में एडीएमएम तथा एडीएमएम प्लस को सहयोग देने की बात दोहराई गई।

अपनी 24वीं मंत्री स्तरीय बैठक में एआरएफ ने अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग तथा रचनात्मक वार्ता द्वारा एआरएफ की विभिन्न कार्य योजनाओं को लगातार मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। जुलाई 2011 में एआरएफ की 11वीं बैठक में स्वीकृत समुद्री सुरक्षा पर एआरएफ की कार्य योजना को मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा तथा संरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण को मजबूत करने, अवैध गैरकानूनी तथा अनियंत्रित मछली मारने और अन्य समुद्री अपराधों पर एआरएफ तथा आसियान के अन्य तंत्रों, जैसे, एएमएफ तथा ईएएमएफ, एडीएमएम, एडीएमएम प्लस तथा एशिया में समुद्री डाकों एवं हथियारबंद डकैतियों पर लगाम कसने में सक्षम पाया (रीसीएएपी)।

सामाजिक सांस्कृतिक आयाम

आसियान समुदाय के गठन में सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ है। आसियान सिर्फ सरकारों, उद्यमियों तथा गैर-सरकारी संगठनों का संघ नहीं है, बल्कि क्षेत्र की जनता के बीच सम्बंधों के निर्माण तथा मजबूती लाने का भी माध्यम है। आसियान समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक स्तम्भ का एक महत्त्वपूर्ण भाग है मानव संसाधान का विकास। सदस्य देशों के अंदरूनी विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप आसियान देशों ने अपने आसियान विजन 2020 में आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय (एएससीसी) के निर्माण का विचार किया, जिसे 2015 में आरम्भ किया गया था। आसियान समुदाय ने माना कि आसियान के संस्थापकों का क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास, क्षेत्रीय शांति तथा सुरक्षा, सहयोग, प्रशिक्षण और शोध में आपसी सहयोग, जीवन शैली में सुधार, दक्षिण-पूर्वी एशिया से जुड़े अध्ययनों का विकास तथा क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सहयोग का लक्ष्य परिलक्षित हो रहा है। इसकी मदद से:

- 1.25 डॉलर प्रति दिन कमाने वालों की संख्या पिछले दो दशकों में 2 में से 1 की बजाय अब 8 में 1 हो गई है,
- मातृ मुत्यु दर 2000 में प्रति 100,000 में 371.2 से घटकर 2012 में 103.7 हो गई है,
- शहरी झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या 2000 में 40% से घटकर 2012 में 31% हो गई है,
- प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकरण की दर 1999 में 92% से बढ़कर 2012 में 94% हो गई है,
- संसद में महिलाओं की भागीदारी 2000 में 12% से बढ़कर 2012 में 18.4% हो गई है,
- आसियान क्षेत्र में 38 आसियान प्राकृतिक धरोहर पार्क तथा 24 यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर दर्ज किये गए हैं।

अब भी कुछ चुनौतियां हैं, जिनका आसियान क्षेत्र में पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो पाया है। शिक्षा का क्षेत्र, विशिष्ट समुदायों का अलगाव, हिंसा में वृद्धि तथा धार्मिक कट्टरपंथ, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता, तथा

कई अन्य चुनौतियां अब भी राष्ट्र निर्माण और पूरे क्षेत्र के विकास में बड़ी बाधा बनी हुई हैं। सामाजिक एकीकरण की महत्त्वपूर्ण अवधारणा घरेलू राजनीतिक एजेंडा में परिवर्तन तथा एएससीसी की उपलब्धियों पाने में महत्त्वपूर्ण होगी। एकल समुदाय के निर्माण तथा एकीकरण की प्रक्रिया में अभिजात्य वर्ग के बजाय आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, जो यूरोप में संभव हो सका है। "समुदाय" निर्माण के समय प्रोत्साहन, सहायता तथा आवश्यक हो, तो आसियान सदस्यों में सुशासन को प्रोत्साहन देना, कानून को मजबूती से लागू करना, एक समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण, मानवाधिकारों की सुरक्षा तथा प्रतिनिधि लोकतंत्र के निर्माण में मदद करनी चाहिए।

भारत तथा आसियान, दोनों सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से स्वयं को समावेशी समाज में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो पारस्परिक जागरुकता, व्यापक परन्तु केन्द्रित संवाद तथा एक-दूसरे के अनुभवों तथा सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। वर्तमान सरकार नियंत्रित आद्योपान्त दृष्टिकोण की स्पष्ट सीमाएं हैं। इसे युवाओं, महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों को वार्ता में शामिल कर मजबूत बनाने की आवश्यकता है, जो सभी आसियान देशों तथा देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तर-पूर्वी भारत, पूर्वी भारत तथा पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व करते हों। आसियान तथा भारत के बीच संस्थागत सम्बंध, भाषा तथा सांस्कृतिक केन्द्र तथा छात्रों के आदान-प्रदान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग की भारी संभावनाएं हैं। भारत तथा इसके सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के बारे में अब भी आसियान देशों में रहनेवालों लोगों को कम जानकारी तथा ज्ञान है। इस दरार को दूर करने के लिए संयुक्त प्रणाली तैयार की जा सकती है। कलाकारों, सांस्कृतिक कलाओं से जुड़े व्यक्तित्वों, विचारकों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों को दोनों भौगोलिक क्षेत्रों की राष्ट्रीय राजधानियों से इतर अन्य प्रमुख शहरों से परिचय कराया जा सकता है। सरकार तथा उद्यमियों को आम लोगों को आपस में सम्बंध बनाने के लिए मंच तैयार करने तथा आवश्यक वित्तीय मदद के लिए पहल करनी चाहिए। इसी प्रकार बौद्ध, हिन्दू तथा इस्लाम से जुड़े पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहन देने के अलावा आसियान देशों तथा भारत में पर्यटकों के भ्रमण के लिए पैकेज तैयार करना चाहिए, ताकि सांस्कृतिक सम्बंध विकसित हो सकें तथा उन क्षेत्रों की पहचान हो सके, जिनके द्वारा भारत एवं आसियान देशों के नागरिक एक-दूसरे के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक तथा सभ्यता के आधार पर जुड़ सकें।

उपसंहार

आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका गठन न सिर्फ क्षेत्रीय विकास एवं सहयोग के लिए, बल्कि सभी आसियान देशों को अपनी क्षेत्रीय सीमा के बाहर से आनेवाली चुनौतियों का सामना करने के लिए किया गया था। सदस्य देशों के बीच बढ़ती आर्थिक असामनता, नागरिक समाज में बढ़ती असहिष्णुता तथा सरकारी तंत्र के प्रति निराशा (विशेषकर थाईलैंड, म्यांमार तथा फिलिपींस में) उन क्षेत्रों को निरन्तर चुनौतियां दे रही हैं, जो आसियान के सफलतापूर्वक क्रियाकलाप का अभिन्न अंग हैं। आसियान के गठन की 50वीं वर्षगांठ पर आसियान के केन्द्रीकरण तथा एक समुदाय के निर्माण पर बल दिया गया है।

आसियान की 50वीं वर्षगांठ महोत्सव के एक भाग के रूप में किये गए विचार-विमर्श द्वारा भविष्य में मजबूत होनेवाले सहयोग के आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयत्न किया गया, साथ ही विभिन्न परियोजनाओं तथा समेकित प्रयासों की सराहना की गई, जिन्होंने ना सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष की, बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के आर्थिक सम्बंधों को मजबूत किया है। हालांकि, आसियान के भीतर नेतृत्व परिवर्तन तथा सरकारों से राष्ट्रवाद के अप्रत्याशित प्रदर्शन के कारण ये कहना मुश्किल है कि दक्षिणी चीन सागर में तनाव कम करने में मदद

मिलेगी अथवा नहीं, क्योंकि कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं है, जिसके कारण भविष्य में आसियान के भीतर तनाव तथा चुनौतियों के बने रहने की आशंका है।

भारत तथा आसियान देशों ने संयुक्त भागीदारी, सहयोग तथा एक-दूसरे की क्षमताओं को समझते हुए तथा एक-दूसरे के ज्ञान को मजबूत करते हुए समानता पर आधारित विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। आसियान तथा भारत के बीच वार्ता की तीस प्रणालियों के साथ एक-दूसरे के बाजार, समानताएं, व्यापारिक परम्पराएं तथा बाजार संस्कृति को समझने के तेज प्रयास किये जा रहे हैं। रक्षा सहयोग, पारम्परिक तथा अपारम्परिक सुरक्षा चुनौतियों, सामाजिक-सांस्कृतिक बंधन तथा सभ्यताओं के जुड़ाव के द्वारा एक-दूसरे के साथ सम्बंध स्थापित करने की दिशा में आसियान भारत का अभिन्न सहयोगी रहा है। भारत की विदेश नीति में आसियान का महत्त्वपूर्ण स्थान है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत के 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी आसियान देशों के राष्ट्र प्रमुखों की मुख्य अतिथि के रूप में मेजबानी के द्वारा भारतीय नेतृत्व ने दर्शा दिया है कि आसियान देशों के साथ उसकी निकटता में वृद्धि हुई है तथा वार्ता की 25वीं वर्षगांठ, शिखर सम्मेलन के 15 वर्ष एवं रणनीतिक सहयोग के पांच वर्षों में उसे पूरा महत्त्व दिया गया है।

****

**डॉ. तेमजेनमेरेन ओ तथा डॉ. ध्रुबज्योति भट्टाचार्जी, आईसीडब्ल्यूए, विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में शोध अध्येता हैं*

डिस्क्लेमर:उपरोक्त विचार शोध अध्येताओं के निजी विचार हैं तथा परिषद के विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते।